



Us 100% / 0 % Uk

रुस से तेल खरीदने पर भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ की तैयारी

भारत- यूके एफटीए लागू : व्हिस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स होंगे सस्ते

वॉशिंगटन डीसी ● एजेंसी

अमेरिका ने रुस से तेल खरीदने वाले देशों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी सीनेट में रुस पर प्रतिबंधों से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया गया है। इसमें रुस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।

बिल के मुताबिक भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। यह बिल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के समर्थन से लाया जा रहा है। इसका मकसद रुस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना है, ताकि उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर हो सके।

इसके तहत रुस के अधिकारियों, शैडो बैंकर बेड़े, केंद्रीय बैंक और सरकारी ऊर्जा परियोजनाओं पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। पहले बिल के शुरुआती मसौदे में 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 100% कर दिया गया।

अगर यह बिल पास हो जाता है, तो अमेरिका पहली बार किसी देश पर सिर्फ इसलिए टैरिफ लगाएगा, क्योंकि वह रुस से तेल खरीदकर उसकी कमाई बढ़ा रहा है।

यूरोपीय देशों को टैरिफ में राहत देगा अमेरिका- रुस से प्राकृतिक गैस खरीदने वाले चीन, फ्रांस, जापान, हंगरी और बेल्जियम को भी इसके दायरे में रखा गया है। हालांकि, जो देश रुस की कुल गैस निर्यात



भारत ने पिछले महीने आधे से ज्यादा तेल रुस से खरीदा

- भारत ने जून 2026 में रुस से रिकॉर्ड 26.1 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा, जो देश के कुल तेल आयात का 52.4% था। यानी पिछले महीने भारत में आयात होने वाले हर दो बैरल तेल में एक से ज्यादा बैरल रुस से आया।
- रुस लगातार भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है। मई के मुकाबले जून में रुस से तेल आयात में करीब 39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

का 15% से कम आयात करते हैं और अपनी निर्भरता घटाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं, उन्हें छूट मिल सकती है।

सीनेट में पेश बिल के तहत 15 यूरोपीय देशों को प्रस्तावित 100% टैरिफ से छूट दी गई है। इन देशों को राहत इसलिए दी गई है, क्योंकि ये रुस से 15% से कम प्राकृतिक गैस खरीदते हैं और धीरे-धीरे उस पर अपनी निर्भरता भी कम कर रहे हैं।

डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमथल ने कहा कि यह बिल यूरोपीय सहयोगियों के खिलाफ नहीं है। इसका निशाना सिर्फ वे देश हैं, जो अब भी रुस के तेल कारोबार को सबसे ज्यादा आर्थिक सहारा दे रहे हैं।

बिल में रुस के ऊर्जा उद्योग, वित्तीय संस्थानों, रक्षा औद्योगिक ढांचे, कारोबारियों और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।

नई दिल्ली ● एजेंसी

भारत में UK की कारें, व्हिस्की, कपड़े और फुटवियर आज से सस्ते मिलेंगे। आज से भारत-UK के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। यानी अब भारत के 99% सामानों को UK में जीरो टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं UK के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर आयात होंगे।

इससे 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर 120 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। करीब 3 साल में 14 राउंड की बातचीत के बाद 24 जुलाई 2025 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटिश व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने पीएम नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर की मौजूदगी में इस समझौते पर साइन किए थे।

ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने कहा- 'ऐतिहासिक पल' - इस व्यापार समझौते के लागू होने से पहले भारत में UK की हाई कमिश्नर लैंडी कैमरन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'उल्टी गिनती शुरू हो गई है! UK और भारत इस बात पर सहमत हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। यह आधुनिक यूके-भारत पार्टनरशिप के लिए ऐतिहासिक पल है। यह दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए ग्रोथ के नए युग की शुरुआत करेगा।'

क्या-क्या फायदा होगा...

UK से आयात होने वाले सामानों पर औसत टैरिफ 15% से घटकर 3% होगा। 85% सामान 10 साल में पूरी तरह टैरिफ-मुक्त होंगे।



व्हिस्की और जिन: UK से आयात होने वाली स्कोच व्हिस्की और जिन पर भारत का टैरिफ 150% से घटकर 75% हो जाएगा। बाद में समझौते के दसवें साल तक इसे घटाकर 40% कर दिया जाएगा। उदाहरण- 5000 रुपए की स्कोच बॉटल 3500 रुपए में मिलेगी।

लगजरी कारें: UK की कारों (जैसे जगुआर लैंड रोवर, रोल्स रॉयस) पर टैरिफ 100% से कोटा सिस्टम के तहत 10% तक आ जाएगा। इससे ये कारें 20-30% सस्ती हो सकती हैं।

खाद्य और पेय पदार्थ: UK से आयात होने वाले सैल्मन, लैब, चॉकलेट, बिस्किट और सांपट ड्रिक्स पर टैरिफ कम होगा। इससे ये उत्पाद सस्ते होंगे।

कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइस: UK के कॉस्मेटिक्स, मेडिकल उपकरण और एग्रोस्पेस प्लांट्स पर कम टैरिफ से ये सामान सस्ते

होंगे। टैरिफ 15% से घटकर 3% पर आ जाएगा। **फैशन और कपड़े:** ब्रिटेन से आने वाले ब्रांडेड कपड़े, फैशन प्रोडक्ट्स और होमवेयर भी सस्ते होंगे। वहीं फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कम कीमत पर मिलेंगे।

रुस पर सख्ती वाले बिल को दोनों दलों का समर्थन

सीनेट में पेश रुस-विरोधी टैरिफ बिल को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, दोनों दलों का समर्थन मिला है। इसे अमेरिकी राजनीति में 'बाइपार्टिसन बिल' कहा जाता है। यानी ऐसा प्रस्ताव जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत हों।

अमेरिका में कई बड़े राजनीतिक मतभेदों की वजह से अटक जाते हैं। लेकिन जब दोनों दल किसी बिल के साथ खड़े होते हैं, तो उसके कांग्रेस से पारित होने की संभावना काफी बढ़ जाती है।

भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट का डेटा लीक, सुरक्षा पर बड़ा साइबर खतरा

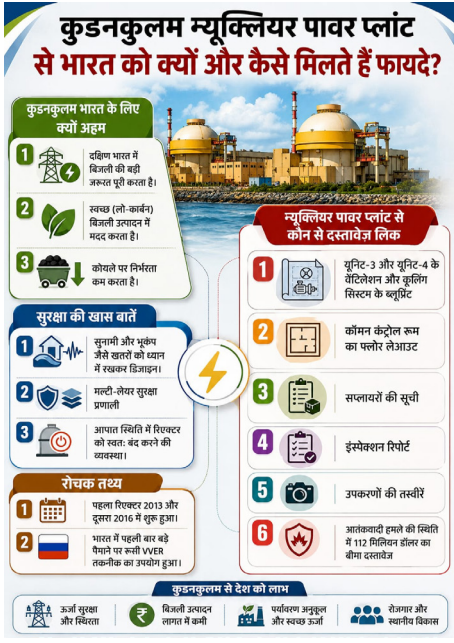
डार्क वेब पर लीक हुई न्यूक्लियर प्लांट की 19 हजार गोपनीय फाइलें

नई दिल्ली ● एजेंसी

भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम से जुड़े हजारों दस्तावेज लीक हो गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, हैकर्स ग्रुप 'वर्ल्ड लीक्स' ने डार्क वेब पर इन दस्तावेजों को अपलोड करने का दावा किया है। इनमें पावर प्लांट के कुछ हिस्सों के ब्लूप्रिंट, सप्लायर्स की लिस्ट, कंट्रोल रूम और अन्य रिकॉर्ड सार्वजनिक किए गए। सर्वर मई में हैक हुआ था, जून में दस्तावेज लीक का दावा किया गया। इसकी जानकारी अब सामने आई है।

तमिलनाडु के कुडनकुलम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने माना है कि थर्ड-पार्टी डेटा सेंटर कंपनी योद्धा का सर्वर हैक किया गया। इसकी जानकारी सरकार को दे दी गई है।

परमाणु सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि डार्क वेब पर मौजूद ये दस्तावेज अगर असली हैं, तो इनके जरिए कोई हमलावर न्यूक्लियर पावर प्लांट के सपोर्ट सिस्टम, सप्लाय चैन और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ सकता है, जिससे सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है।



रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी

IRCTC की नई बीटा वेबसाइट लॉन्च, बदला टिकट बुकिंग का अंदाज; हुए ये चार बड़े बदलाव

नई दिल्ली ● एजेंसी

रेल मंत्री ने छात्रों से किया अपना वादा तय समय पर पूरा कर दिया है। यात्रियों को बेहतर टिकट बुकिंग अनुभव देने के लिए आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन बुधवार को लॉन्च कर दिया गया। नई वेबसाइट को यूजर्स के लिए ट्रायल के तौर पर उपलब्ध कराया गया है, ताकि यात्री इसके नए डिजाइन और सुविधाओं का अनुभव लेकर अपने सुझाव दे सकें।

आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट को यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें आसान नेविगेशन, साफ-सुथरा इंटरफेस और टिकट बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। वेबसाइट में किए गए सुधारों



के सुझाव मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT) के छात्रों ने रेल मंत्री के साथ बातचीत के दौरान दिए थे।

पंडित धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिगराम को जेल भेजा

छतरपुर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिगराम गंग और उसके एक साथी को छतरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शालिगराम समेत 4 लोगों पर जमीन विवाद में मोतीलाल कुशवाहा नाम के युवक को गोली मारने का आरोप है। मामला राजनगर में गौशाला के पीछे की जमीन के विवाद से जुड़ा है। पुलिस ने शालिगराम और अंकित मिश्रा को बुधवार शाम को कोर्ट में पेश किया। जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। दो आरोपी अब भी फरार हैं। घायल मोतीलाल कुशवाहा राजनगर थाना इलाके के कोड़ा गांव का रहने वाला है। उसे मंगलवार को गोली लगने के बाद गंभीर हालत में छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मोतीलाल ने पुलिस को बताया था- शालिगराम गंग मेरी जमीन छीनना चाहते हैं।



नोएडा में 4 मंजिला बिल्डिंग में आग, 2 जिंदा जले

नोएडा। नोएडा में बुधवार सुबह 11 बजे 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। हादसे में 2 लोग जिंदा जल गए। एक बच्चा और एक युवती गंभीर रूप से झुलस गए। फायर ब्रिगेड ने सीढ़ियों के सहारे 50 परिवारों का रेस्क्यू किया। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि बिल्डिंग के बेसमेंट में इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज हो रही थी। इसी दौरान उसमें धमाका हुआ और आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। 30 से 40 बाइकें जलकर राख हो गईं। धुआं उठता देखकर बिल्डिंग के आसपास रहने वाले सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए। बिल्डिंग के निचले हिस्से में फंसे लोग बाहर निकल गए, लेकिन ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोग फंस गए। सूचना



पड़ा। इसके बाद पाइप जोड़कर आग पर काबू पाया गया। इसमें करीब 3 घंटे लगे। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, उसकी छत से सामने वाली बिल्डिंग तक सीढ़ियां लगाकर पुल बनाया। फिर उसके सहारे लोगों को दूसरी बिल्डिंग में सुरक्षित पहुंचाया।

पर फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन भीड़ और संकरी गलियों के चलते वे बिल्डिंग तक नहीं पहुंच सकीं। ऐसे में गाड़ियों को सड़क पर ही खड़ा करना पड़ा। इसके बाद पाइप जोड़कर आग पर काबू पाया गया। इसमें करीब 3 घंटे लगे। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, उसकी छत से सामने वाली बिल्डिंग तक सीढ़ियां लगाकर पुल बनाया। फिर उसके सहारे लोगों को दूसरी बिल्डिंग में सुरक्षित पहुंचाया।

संपादकीय

भाजपा सरकार हृदयहीन, विपक्ष असंवेदनशील, मौका परस्त?

स माजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांकोरच जताता पार्टी के साथ अनशन में भूखहड़ताल कर रहे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद् सोम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील की है। 17 दिन अनशन के पूरे हो चुके हैं और उनका वजन 8 किलो से ज्यादा कम हो चुका है। डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं उन्होंने उनकी जिंदगी की लोकेन्द्र चिंता जताई है। इस चिंता को देखते हुए विपक्ष ने भी बयान-बाजी करना शुरू कर दिया है। सपा नेता अखिलेश यादव ने सोम वांगचुक से अपील करते हुए कहा, भाजपा सरकार के लिए किसी के जीवन का कोई महत्व नहीं है। हम उनसे विनम्र अपग्रह करते हैं कि वह अनशन तोड़ दें। उनकी जान मानवता और पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है। लोकतंत्र के लिए जिस भाजपा नेतृत्व वाली सरकार को जगाने के लिए वह अनशन पर हैं वह एक सिद्धांतहीन, भ्रष्ट तंत्र, अस्वेदनीशीलता और हृदयहीनता वाला सरकार है। उससे एक लिए किसी के भी त्याग का कोई महत्व नहीं है। पिछले एक सप्ताह से विपक्ष के नेता सोम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस लड़ाई में साथ देने के लिए विपक्ष और आम जनता जिनकी वह लड़ाई लड़ रहे हैं वह सब शांति के साथ तमाशा देख रहे हैं। यदि आम जनता और विपक्ष जिम्मेदार और संवेदनीशील होता तो वह उनके समर्थन में आंदोलन और इस लड़ाई को लड़ने के लिए उनके साथ खड़ा होता। यह तो हुआ नहीं, सपा विपक्ष सरकार को कोस रहा है, लेकिन सरकार अनशन के लिए ना तो विपक्ष एकजुट हो रहा है ना ही आम जनता अपनी लड़ाई खुद लड़ने आ रही है।

भाजपा सरकार की स्पष्ट धारणा है, जनता को यदि तकलीफ होगी तो वह स्वयं सड़कों पर उतर आएगी, लेकिन यदि जनता सड़कों पर नहीं है तो इसका मतलब उसने कोई तकलीफ नहीं है। विपक्ष यदि एकजुट नहीं है ऐसी स्थिति में सरकार वह मानकर चलती है कि उसे और उसकी सरकार की नीतियों पर जनता का समर्थन प्राप्त है। ऐसी स्थिति में पर उपदेश कुशल बहुतेरे की तरह सभ अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर टालकर अपने आपको बेहतर और सर्वश्रेष्ठ दिखाते हुए अपने हितों की पूर्ति करने के लिए अपने कर्तव्य से पूरी तरह से भटक चुके हैं। जो सरकार में बैठे हैं वह सत्ता के सुख भोग रहे हैं। विपक्ष में बैठे सत्ता तक पहुंचने के लिए अलग-अलग राजनीति कर रहे हैं। जनता के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। देश की समस्याओं के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। जितने भी विपक्षी राजनीतिज्ञ दल हैं वह अपने राजनीतिज्ञ हितों और पार्ष्णिक हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के संरक्षण और लोकतंत्र तथा गरीबों की यदि उन्हें चिन्ता होती तो सारा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ता। गांगुलु जैसे पर्यावरण विद्व जय पर्यावरण और स्वतंत्रता के साथ विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ने के लिए अनशान जैसे कठोर कदम उठाते हैं, ऐसे समय पर भी यदि विपक्ष एकजुट नहीं होता तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है।

इसके पहले भी पर्यावरणविद् प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की मौत अनाशन के दौरान हो चुकी है। 111 दिन वे आमरण अनाशन पर बैठे रहे। साता विश्व अलग-थलग रहा। सरकार के लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा माफूक है। सरकार सोचती है, जब जनता और विश्व उनकी नीतियों और सत्ता से सहमत है, तभी तो कोई विशेष दर्ज नहीं करा रहा है। जब तक संपूर्ण विश्व ईमानदारी के साथ संविधान, लोकतंत्र तथा आम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट नहीं होगा, जनता को जब तक वह यह विश्वास नहीं दिलाएगा कि विश्व जनता की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसी स्थिति में जनता उनके साथ कैसे खड़ी होगी? इसे आसानी से समझा जा सकता है। कॉन्क्रेट जनता पार्टी एक ऐसा मंच है जिसने मुख्य-न्यायाधीश द्वारा युवाओं को कॉन्क्रेट कहने के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद सोलिकन मीडिया पर बनी थी। इस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन इसी के बाद पर जाकर सोमन वांगचुक ने अनाशन शुरू कर दिया, जिसके कारण इतने बड़े पर्यावरण और शिक्षा के मुद्दे में वह एक तरह से अलग-थलग पड़ गए हैं। सरकार भी इसी का फायदा उठा रही है। विश्व भी कॉन्क्रेट जनता पार्टी के मंच पर जाने से बच रहा है। लेकिन यह एक ऐसा मामला है जब सारा लोगों को मिलकर पर्यावरण और छात्रों की मांग उठानी चाहिए। राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम जनता को भी इस लड़ाई में साथ आना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जिस तरह से पहले भी अनाशन और आंदोलन के दौरान कई लोगों की जान भेंट चढ़ चुकी है, आशंका है ऐसी ही बात भेंट सोमन वांगचुक की चढ़ सकती है।

प्रशिक्षण के
ए तीन महीने,
छह महीने या
क वर्ष के लिए
रजिस्ट्रेशन
कराना होता
है। कोर्स पूरा
होने के पश्चात्
प्रमाणपत्र दिया
जाता है, जो
गण में मान्य
है और इस
प्रमाणपत्र
के आधार पर
आसानी से
रोजगार प्राप्त
किया जा सकता
है। युवा वर्ग
ज में अधिक
न्यायसंगत,
समान और
प्रगतिशील
अवसरों तथा
समाधानों की
खोज कर रहा है,

लेखक- ललित गर्ग

आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से प्रारम्भ होकर दस दिनों तक चलने वाली भगवान श्री जगन्नाथ की रथयात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, लोकआस्था, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक दर्शन का विराट उत्सव है। पुरी की यह महायात्रा हजारों वर्षों की परम्परा का जीवंत प्रतीक है, जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। इसी कारण इसे "महायात्रा" कहा जाता है। भारत के चार धामों में प्रतिष्ठित श्री जगन्नाथ धाम की यह यात्रा देश ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व के करोड़ों श्रद्धालुओं के आकर्षण का केन्द्र बनती है। वर्ष 2026 की रथयात्रा भी अपार श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई जा रही है, किन्तु इस बार इसके साथ एक नया विवाद भी जुड़ गया है। देश एवं विदेश के अनेक स्थानों पर इस्कॉन द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग तिथियों पर रथयात्राएं आयोजित किए जाने पर कुछ धार्मिक एवं परम्परावादी संगठनों ने आपत्ति व्यक्त की है। उनका मत है कि जगन्नाथ रथयात्रा की तिथि वही होनी चाहिए जो पुरी श्रीमंदिर द्वारा निर्धारित होती है। दूसरी ओर इस्कॉन का तर्क है कि विदेशों में स्थानीय प्रशासन की अनुमति, सार्वजनिक अवकाश, मौसम तथा अन्य व्यावहारिक कारणों से कभी-कभी तिथि में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। यह विवाद केवल तिथि का नहीं, बल्कि परम्परा और वैश्विक विस्तार के बीच संतुलन खोजने का विषय बन गया है।

वास्तव में यह समझना आवश्यक है कि पुरी का ही
रथयात्रा और अन्य स्थानों पर आयोजित रथयात्राओं का
स्वरूप अलग-अलग हो सकता है, किन्तु उनका मूल उद्देश्य
भगवान् जगन्नाथ की भक्ति, लोककल्याण और धर्मप्रचार ही
है। यदि परम्परा का सम्मान बना रहे और श्रद्धा अक्षुण्ण रहे
तो मतभेद संवाद के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। धर्म
का मूल स्वस्व जोड़ना है, विभाजन करना नहीं। पुरी का
श्रीमंदिर भगवान् जगन्नाथ का मुख्य धाम है। लगभग 800
वर्ष पुराने इस मंदिर में भगवान् श्रीकृष्ण जगन्नाथ स्वस्व में
अपने बड़े भाई बलदेव में बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं।
प्रतिवर्ष केवल एक बार तीनों देव विग्रह अपने गम्भीर से
बाहर निकलकर भक्तों को दर्शन देते हैं। यही इस यात्रा के
समसे बड़ी विशेषता है। सामान्य दिनों में जहाँ भगवान् के
दर्शन सीमित होते हैं, वहीं रथयात्रा में प्रत्येक व्यक्ति बिना
किसी भेदभाव के भगवान् के साक्षात् दर्शन कर सकता है।

यात्रा की तैयारियां अक्षय तृतीया से प्रारम्भ हो जाती हैं। उसी दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के तीनों विशाल रथों का निर्माण आरम्भ होता है। प्रत्येक वर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। यद्यपि उनका स्वरूप और आकार सदियों से

समान रहता है, फिर भी प्रत्येक वर्ष नई लकड़ी, नई सजा और नवीन निर्माण किया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ गरुडध्वज (कपिलध्वज), बलभद्र का तालध्वज तथा सुभद्रा का दर्पदलध्वज अथवा पद्मध्वज कहलाता है। इन रथों के निर्माण को प्रक्रिया केवल शिल्पकला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना मानी जाती है। कारीगर विशेष धार्मिक नियमों का पालन करते हुए इन्हें बनाते हैं। यह परम्परा हमें यह संदेश देती है कि प्रत्येक वर्ष मनुष्य भी अपने भीतर की ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और लोभ को त्यागकर स्वयं का नव-निर्माण करे।

रथयात्रा के पीछे अनेक पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं। कहा जाता है कि एक बार सुभद्रा ने द्रुपदा का नगर देखने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान श्रीकृष्ण और बलराम ने उन्हें अलग रथ पर बैठकर नगर भ्रमण करवाया। उन्हीं स्मृति में तीनों भाई-बहनों की संयुक्त रथयात्रा निकाली जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान की अर्पण प्रतिमाओं का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था, जो आज भी जगन्नाथ संस्कृति की विशेष पहचान है। इस महायात्रा का एक अत्यंत मार्मिक पक्ष यह भी है कि स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान अस्तस्फुट माने जाते हैं और लगभग पन्द्रह दिनों तक सार्वजनिक दर्शन नहीं देते। इसके पश्चात वे रथों पर आरुढ़ होकर अपनी मौसी के घर गुण्डिका मेंर जाते हैं। वहां नौ दिनों तक विश्राम करते हैं और फिर बहुड़ा यात्रा के माध्यम से पुनः श्रीमंदिर लौटते हैं। लौटते समय भगवान का पोड़ा पीठा प्रघटन करना, पंचमी को देवी लक्ष्मी का रुष्ट होकर रथ का पहिया तोड़ना तथा बाद में भगवान द्वारा उन्हें मनाने की परम्परा भक्तिभाव एवं मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण है।

पुरी की रथयात्रा का एक अन्य अद्भुत दृश्य छेरा पहारा है। गजपति महाराज स्वयं स्वर्ण निर्मित झाल से रथों के मार्ग की सफाई करते हैं। यह परम्परा संदेश देती है कि ईश्वर के समक्ष राजा और सामान्य व्यक्ति सभी समान हैं। सत्ता का सर्वोच्च पाठ भी सेवा से बढ़ा नहीं हो सकता। थोथाना के समय जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद भी विशेष आकर्षण का केन्द्र होता है। विश्व की सबसे बड़ी मंदिर रसोईयों में से एक इस रसोई में मिट्टी के पात्रों में प्रसाद बनाया जाता है। दाल, चावल, सब्जियाँ, मालपुआ, गुजामूंग, लाई, नारियल तथा अनेक प्रकार के व्यंजन अत्यंत अतिथि मूल्य पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। यह प्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि समानता और साझेदारी का प्रतीक है।

धार्मिक ग्रन्थों में रथयात्रा का अत्यन्त महत्व बताया गया है। स्कन्द पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण तथा उत्कल खण्ड में भगवान् जगन्नाथ की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। मान्यता है कि रथयात्रा के दर्शन एवं रथ को स्पर्श करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं तथा रथ खींचने वाले

को मोक्ष का अधिकारी माना गया है। यद्यपि इन मान्यताओं का अध्यात्मिक अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन-रथ को धर्म, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलता है, वही सार्वत्रिक मुक्ति प्राप्त करता है। जगन्नाथ रथयात्रा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सामाजिक समरसता है। इस अवसर पर जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र अथवा सम्प्रदाय का कोई भेद नहीं रहता। लाखों श्रद्धालु एक साथ रथ की रस्सी खींचते हैं। यह वह क्षण होता है जब सभी केवल पूजा-पद्धति न रहकर सामाजिक एकता का उत्सव बन जाता है।

आज यह यात्रा केवल पुरी तक सीमित नहीं रही। भारत के लगभग सभी प्रमुख नगरों सहित अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और अनेक यूरोपीय देशों में भी गजपात्र रथयात्रा आयोजित होती है। विशेष रूप से इस्कॉन ने इस परम्परा को वैश्वक पदान्तरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। करोड़ों विदेशी भक्तों ने इसी माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण जैसे जनप्राप्त संस्कृति को जाना है। इसलिए यदि कहीं तिथियों को लेकर व्यावहारिक परिवर्तन भी किए जाएँ तो उसे पीछे धार्मिक अवधाना नहीं दें, बल्कि स्थानीय व्यवस्थाओं को विश्वासा भी हो सकती है। फिर भी यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि जहाँ तक सम्भव हो, श्रीमंदी की परम्परा और निर्मातृ-तिथि का सम्मान किया जाए, ताकि सम्पूर्ण विश्व में एकामस्ता का संदेश और अधिक सुदृढ़ हो।

दार्शनिक दृष्टि से रथ मनुष्य के शरीर का, भगवान आत्मा का तथा रथ को खींचने वाली रिसस्यौं समाज और लोकशक्ति का प्रतीक हैं। आत्मा तभी सार्थक होती है जब समाज सहयोग करे और समाज तभी श्रेष्ठ बनता है जब उसके केन्द्र में ईश्वर, नैतिकता और आत्मशुद्धि का भाव हो। यही कारण है कि जगन्नाथ रथयात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मविशुद्धि, लोकमंगल, समरसता, सेवा और आध्यात्मिक जागरण का अनुपम पर्व है। वर्तमान समय में जब समाज अनेक प्रकार के वैचारिक, सामाजिक और धार्मिक विभाजनों से गुजर रहा है, तब भगवान जगन्नाथ की यह महायात्रा हमें स्मरण कराती है कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य विवाद नहीं, बल्कि संवाद है। वर्चस्व नहीं, बल्कि समन्वय है और बाहरी आडम्बर नहीं, बल्कि अंतःकरण की पवित्रता है। यही इस महायात्रा का सनातन संदेश है कि जीवन का रथ तभी सही दिशा में चलता है जब उसमें श्रद्धा, सेवा, समरसता, आत्मसंयम और लोककल्याण के पहिए समान गति से चलते रहें। यही जगन्नाथ महायात्रा की शाश्वत परिभाषा है और यही इसकी वैश्विक प्राप्तिपंक्ति।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

महिला आरक्षण का ऐतिहासिक क्षण सामने

लेखक - कांतिलाल मांडोत

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कुछ ऐसे अवसर आते हैं जो केवल कानून बनाने की प्रक्रिया नहीं होते बल्कि सामाजिक परिवर्तन की नई दिशा तय करते हैं। महिला आरक्षण का प्रश्न भी ऐसा ही विषय है। वर्षों से देश की आधी आबादी संसद और विधानसभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग करती रही है। अनेक सरकारें आईं और गईं। अनेक समितियां बनीं। अनेक बार विधेयक प्रस्तुत हुआ। बहरसें हुई।

समर्थन और विरोध के स्वर भी सुनाई दिए। लेकिन यह सभना हर बात अधूरा रह गया। अब परिस्थितियाँ बदलती दिखाई दे रही हैं। संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले राजनीतिक माहौल यह संकेत दे रहा है कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को वास्तविकता का रूप देने की तैयारी जेठ हो चुकी है। संसद से महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात सत्ता गश्क के साथ विपक्ष भी सकारात्मक रूप अपनाता दिखाई दे रहा है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को समर्थन देने की घोषणा करी यह स्पष्ट संदेश दिया है कि महिलाओं के अधिकार किसी दल की राजनीति का विषय नहीं होने चाहिए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वे इस ऐतिहासिक पहल में सहयोग करें ताकि वर्षों से लंबित यह सभना अब पूरा हो सके। यह परिपक्व लोकतंत्र की पहचान है कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर राजनीतिक महभेदों से ऊपर उठकर सर्वसम्मति बनाई जाए। महिला आरक्षण का विचार नया नहीं है। इसकी चर्चा तीन दशक से अधिक समय से होती रही। पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षण मिलने के बाद यह सिद्ध हो चुका है कि अवसर मिलने पर महिलाएं नेतृत्व की जगह मिलाव कायम करती हैं। लाखों महिला जनप्रतिनिधियों ने गांव और शहर के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यही अनुभव अब संसद और विधानसभाओं तक पहुंचाने का समय है।

भारत की आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग आधी है लेकिन संसद और अधिकांश विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है। लोकतंत्र तभी मजबूत माना जाएगा जब निर्णय लेने वाली संस्थाओं में समाज के सभी वर्गों की समान भागीदारी हो। महिला आरक्षण इसी लोकतांत्रिक संतुलन को स्थापित करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। इस



बार राजनीतिक परिस्थितियाँ पहले से अलग हैं। सर्वोत्कृष्ट रूप से महिला आरक्षण लागू करने की इच्छा नहीं रही है। विपक्ष का बड़ा हिस्सा भी इसका समर्थन कर रहा है। ऐसे में वर्षों से चली आ रही राजनीतिक खींचतान समाप्त होती दिखाई दे रही है। यदि सभी दल सहमत हों तो यह विधेयक आसानी से पारित हो सकता है। भारतीय लोकतंत्र में एक नया अध्याय जुड़ सकता है।

अब प्रश्न यह भी उठता है कि जब कांग्रेस के नेता हवाई सरकार के पास लंबे समय तक सत्ता रही, तो कौन अक्सरों पर मजबूत राजनीतिक स्थिति भी थी। महिला आरक्षण का सपना पूरा क्यों नहीं हो सका? संसदवाली इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से स्वयं को महिला अधिकारों की समर्थक पार्टी बताने की है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस सरकार के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को आगे बढ़ाने का प्रयास अवश्य हुआ। राज्यसभा में इसे पारित भी कर दिया। लेकिन लोकसभा में इसे अंतिम मंजूरी नहीं मिल सकी। इसके पीछे सचवाणी दलों के विरोध और विधायी राजनीतिक समीकरणों का हवाला दिया गया। कुछ राजनीति के भीतर इसकी भी मांग कर रहे थे जब कुछ अन्य दलों ने इसका खुला विरोध किया। अतः इन मतभेदों को दूर करने और आवश्यक राजनीतिक

सहमति बनाने में सफल नहीं हो सकी। परिणाम यह हुआ कि विधेयक कानून नहीं बन पाया।

यही वह बिंदु है जहाँ कांग्रेस की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर प्रश्न उठते हैं। यदि किसी सरकार की प्राथमिकता वास्तव में किसी ऐतिहासिक सुधार को लागू करना हो तो वह व्यापक संस्थापित कर राजनीतिक सहमत बनाने का प्रयास करती है। महिला आश्रण के मामले में यह प्रक्रिया पूरी मजबूती से आगे नहीं बढ़ सकी। कई अस्पर ऐसे आए जब सरकार अधिक निर्णायक भूमिका निभा सकती थी लेकिन राजनीतिक जोखिम उठाने से परहेज किया गया। इस लिए यह कदम उचित होगा कि केवल समर्थन व्यक्त कराना पर्याप्त नहीं था बल्कि अंतिम परिणाम तक पहुँचना भी आवश्यक था। आज की परिस्थिति में विपक्ष का समर्थन स्वागत योग्य है। यदि कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल बिना किसी शर्त के महिला आश्रण के पक्ष में खड़े होंगे तो यह देश के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत होगा। इस विषय पर किसी प्रकार के राजनीतिक गिले शिकवे या पुराने विवादों को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। यह समय थ्ये लने का नहीं बल्कि इतिहास बनाने का है। महिला आश्रण केवल महिलाओं के लिए सौ से अधिक करने की व्यवस्था नहीं है। यह राजनीति की कार्यशैली

में व्यापक परिवर्तन का माध्यम भी बन सकता है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से शिक्षा स्वास्थ्य पोषण महिला सुरक्षा बाल कल्याण और सामाजिक विकास जैसे विषयों को अधिक प्राथमिकता मिलने की संभावना बढ़ेगी। विश्व के अनेक देशों का अनुभव भी यही बताता है कि महिलाओं की प्रभावी भागीदारी से लोकतांत्रिक संस्थाएं अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनती हैं।

यह भी याद रखना चाहिए कि आरक्षण का उद्देश्य किसी को विशेष लाभ देना नहीं बल्कि लंबे समय से चली आ रही असमानता को दूर करना है। समाज में महिलाओं ने हर क्षण में अपनी क्षमता सिद्ध की है। विज्ञान खेले सेना न्यायपालिका प्रशासन उद्योग और अंतरिक्ष तक उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। अब राजसून सत्र को लेकर जिस प्रकार राजनीतिक गतिविधियाँ उत्पन्न हुई हैं उससे उम्मीद जगी है कि इस बार केवल चर्चा नहीं होगी बल्कि ठोस परिणाम भी सामने आएगा। सरकार यदि पूरी तैयारी के साथ विधेयक को पारित करेगी तो यह भारतीय संसद की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाएगा। आज देश की करोड़ों महिलाएँ इस ऐतिहासिक निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हैं। वे केवल वादा नहीं बल्कि अधिकार चाहती हैं। वे केवल प्रतीकात्मक सम्मान नहीं बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाग़दारी की भागीदारी चाहती हैं। यही लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ भी है। अब यह स्पष्ट होता चला रहा है कि महिला आरक्षण का सही समय आ चुका है। तीन दशकों से चली आ रही प्रतीक्षा सम्पन्न होने की ओर है। राजनीतिक दलों ने यदि परिपक्वता का परिचय दिया और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा तो आने वाला मानसून सत्र भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा। यह केवल एक कानून नहीं होगा बल्कि आजादी आबादी के सम्मान समान अधिकार और सशक्त भविष्य का नया संकल्प होगा।

न्यूज़ ब्रीफ

टीएमसी के वरिष्ठ विधायक मदन मित्रा बागी गुट में शामिल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में गुणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को बड़ा झटका देते हुए वरिष्ठ नेता और विधायक मदन मित्रा ने पार्ष्व नेतृत्व से दुरी बनाते हुए ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट का दामन थाम लिया है। हालांकि उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। उनका यह फैसला ऐसे समय आया है जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके परिवार से पूछताछ कर रहा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ईडी ने एक दिन पहले ही मदन मित्रा की पत्नी और उनके दो बेटों को पूछताछ के लिए तलब किया था। इसके अगले ही दिन मित्रा ने बागी गुट में शामिल होने की घोषणा कर दी। इसके बाद उन्होंने बागी विधायक दल के नेता ऋतब्रत बनर्जी और अन्य नेताओं के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस वार्ता में मदन मित्रा ने पार्ष्व के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्ष्व संगठन लगातार कमजोर हो रहा है, लेकिन पूरा ध्यान केवल एक व्यक्ति को बचाने पर केंद्रित है।

पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, केवल विदेश यात्रा का दस्तावेज़ : केंद्र सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने फिर स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह केवल देश से बाहर यात्रा करने के लिए पहचान दस्तावेज है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत भारतीय नागरिकों को यह दस्तावेज यात्रा सुविधा के लिए जारी होता है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसे गहन जांच और सत्यापन प्रक्रिया के बाद जारी किया जाता है। इसका संचालन पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और पासपोर्ट नियम, 1980 के कड़े प्रावधानों के तहत होता है। जायसवाल ने महत्वपूर्ण आंकड़ा भी साझा किया कि देश के 8 प्रतिशत से भी कम नागरिकों के पास पासपोर्ट है। इसके पहले, 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर भी विदेश मंत्रालय ने बताया कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का सबूत नहीं। विदेश मंत्रालय ने 2013 के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया था, जिसमें पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया था।

पजामे का नाड़ा खोलना...जैसी टिप्पणियाँ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त,

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराध से जुड़े मुकदमों में न्यायिक संवेदशीलता बनाए रखने के लिए तैयार की गई राष्ट्रीय गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी है। भारत के न्यायिक जस्टिस (सीजेआई) सुर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने देश की सभी अदालतों को मंजूर की गई गाइडलाइंस या हैंडबुक में दिए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। यह कदम अदालतों के फैसलों में एकरूपता और संवेदशीलता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये गाइडलाइंस नेशनल जुडिशल एकेडमी की विशेष समिति ने तैयार की थीं, जिनकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी। सीजेआई के आदेश के अनुसार, इन गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट, सभी हाई कोर्ट और जिला अदालतों की वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही, इन्हें नेशनल जुडिशल एकेडमी सहित सभी प्रदेश न्यायिक अकादमियों, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और विभिन्न विध्वविद्यालयों के विधि विभागों में भी वितरित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये गाइडलाइंस न्यायिक आदेश का हिस्सा बनेंगी। इन दिशा-निर्देशों का पालन केवल अदालतों तक सीमित नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लिए कहा है कि वे सभी पुलिस स्टेशनों को इन हैंडबुक में कही गई बातों का पालन करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें।

देश-विदेश 10 लाख से अधिक भक्तों के पहुंचने की उम्मीद विश्वप्रसिद्ध जगन्नाथ रथयात्रा की शुरुआत आज से

पुरी ● एजेंसी

ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्वप्रसिद्ध रथयात्रा 16 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेगी। इस नौ दिवसीय धार्मिक उत्सव में देश-विदेश से 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। रथयात्रा को लेकर पुरी में तैयारियों का दौर अंतिम चरण में है, तो वहीं होटल और लॉज महीनों पहले ही पूरी तरह बुक हो चुके हैं। ऐसे में प्रोफेसर डॉ शोख मकबूल इस्लाम की चर्चा भी हो रही है, जो कठोपनिषद् के प्रसिद्ध श्लोक का हवाला देते हुए कहते हैं कि जब शरीर स्वयं रथ है, बुद्धि सारथी है और आत्मा उसका स्वामी है, तो अलग रथ की आवश्यकता नहीं।

विश्वप्रसिद्ध रथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को लेकर जिला प्रशासन का कहना है, कि इस वर्ष फरवरी से ही होटल बुकिंग शुरू हो गई थी। मंदिर और रथयात्रा मार्ग के आसपास स्थित होटलों की सर्वाधिक मांग रही है। खासकर जिन होटलों की बालकनी या खिड़कियां रथयात्रा मार्ग की तरफ खुलती हैं, उनके कमरे सबसे पहले बुक हो गए। जैसे ही मांग बढ़ी वैसे ही किराए में भी भारी उछाल आ गया। सामान्य दिनों में 1,500 से 2,000 रुपये प्रतिदिन से मिलने वाले कमरे रथयात्रा के दौरान तीन दिनों के लिए 50 हजार रुपये तक में बुक किए जा रहे हैं। पूरे पुरी शहर में लगभग 1,200 होटल और लॉज हैं, जिनमें अधिकांश पहले से बुक हो चुके हैं।



इस अनूठी परंपरा का आधार है कठोपनिषद् का प्रसिद्ध श्लोक

वे अपनी परंपरा का आधार कठोपनिषद् के प्रसिद्ध श्लोक आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तुज्ज् को बताते हैं। उनके अनुसार, जब शरीर स्वयं रथ है, बुद्धि सारथी है और आत्मा उसका स्वामी है, तो अलग रथ की आवश्यकता नहीं। डॉ. इस्लाम पूरी तरह शाकाहारी हैं और पुरी की परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ को 35 प्रकार के सात्विक भोग अर्पित करते हैं। उनकी यह पहल धार्मिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का अनूठा उदाहरण मानी जाती है।

सुप्रीम कोर्ट से चारा घोटाला में राहत मिलने पर लालू यादव बोले- हां, मैं खुश हूं

घर से बाहर निकलने पर समर्थकों ने किया स्वागत, लालू के साथ सेल्फी भी ली

पटना ● एजेंसी

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर खुशी जाहिर की। अपने आवास से बाहर निकलने पर समर्थकों ने लालू यादव का जोरदार स्वागत किया और उनके साथ सेल्फी ली। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में लालू यादव ने कहा कि हां, मैं खुश हूं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को राहत देते हुए उनकी जमानत रद्द करने और सजा निलंबन के आदेश को समाप्त करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दी गई राहत को बरकरार रखा। चारा घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने



लालू प्रसाद यादव को जमानत देते हुए अंतिम फैसला आने तक उनकी सजा निलंबित रखी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को उनकी लंबित अपराधिक अपील का निपटारा छह महीने के अंदर करने का निर्देश भी दिया। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने मंगलवार को कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश को

करीब सात साल बीत चुके हैं, इसलिए इस स्तर पर उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2018 से लंबित अपील पर अब शीघ्र सुनवाई होनी चाहिए। सीबीआई ने हाईकोर्ट के 12 जुलाई 2019 के आदेश को चुनौती दी थी। सीबीआई का कहना था कि लालू प्रसाद यादव को इस आधार पर सजा निलंबन का लाभ दिया गया

भारत और पोलैंड मिलकर करेंगे हथियार निर्माण

नई दिल्ली ● एजेंसी

भारत के मेक इन इंडिया मिशन में अब एक बहुत ही ताकतवर ग्लोबल पार्टनर की एंट्री हो गई है। अब भारत और पोलैंड मिलकर बेहद आधुनिक और घातक मिलिट्री हथियार बनाने जा रहे हैं, और सबसे खास बात ये है कि ये सारे हथियार पूरी तरह से भारत की जमीन पर ही तैयार किए जाएंगे। खुद पोलैंड के उप विदेश मंत्री और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट व्लादिस्लाव थियोफिल बार्टोंसजेव्स्की ने इस बड़ी पार्टनरशिप का ऐलान किया है। इस खबर के सामने आते ही ग्लोबल डिफेंस मार्केट में जबरदस्त हलचल मच गई है, क्योंकि पोलैंड की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और भारत की विशाल मेन्यूफैक्चरिंग पावर



मिलकर दुनिया भर में तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। यह समझौता केवल हथियारों की खरीद-फरोख्त तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक और तकनीकी सहयोग का नया अध्याय लिखेगा।

भारत और पोलैंड अब मिलकर भारत में ही मिलिट्री से जुड़े हथियार और सिस्टम यानी डिफेंस प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच इस पार्टनरशिप को लेकर गंभीर बातचीत चल रही है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट व्लादिस्लाव थियोफिल बार्टोंसजेव्स्की ने मंगलवार को खुद इस बात की जानकारी दी है। बार्टोंसजेव्स्की ने आईएनएस से बातचीत में कहा, भारत उन खास रक्षा प्लेटफॉर्म में रुचि रखता है, जिन्हें हम बनाते हैं। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इन्हें भारत में कुछ भारतीय हिस्सेदारी के साथ कैसे बनाया जा सकता है। साथ ही, हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ भारतीय प्लेटफॉर्म को पोलैंड में पोलिश भागीदारी के साथ जॉइंट वेंचर के जरिए बनाया जा सकता है। यह

आदान-प्रदान दोनों देशों को एक-दूसरे की विशेषज्ञता से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने आगे कहा, मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए हम सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में अपना सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। हम केवल रक्षा उपकरण बेचने की बात नहीं कर रहे, बल्कि भारत में कुछ चीजों के उत्पादन के लिए मिलकर कंपनियां शुरू करने की संभावनाओं पर भी चर्चा कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान को समझते हैं और चाहते हैं कि इन प्लेटफॉर्म में भारतीय और पोलिश दोनों देशों की भागीदारी हो। पोलैंड के मंत्री ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के महत्व पर भी जोर दिया, उनका मानना है कि इससे दोनों पक्षों के बीच व्यापार को काफी बढ़ावा मिलेगा।

स्थिति को नियंत्रित करने पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात

मणिपुर में असम राइफलस कैंप पर हमला, आगजनी और तोड़फोड़ की

इंफाल ● एजेंसी

मणिपुर के सेनापति शहर में उग्र भीड़ ने असम राइफलस के कैंप पर हमला कर दिया। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि भीड़ ने पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ की। यह हमला सशस्त्र उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे सुरक्षा अभियान को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया। हिंसा में भीड़ ने असम राइफलस के कई वाहनों में तोड़फोड़ की और उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। एक वाहन को आग के हवाले कर दिया, जबकि दो ट्रकों को पलट दिया। घटना में एक आम नागरिक की कार को

भी आग के हवाले कर दिया। मीडिया रिपोर्ट में रक्षा प्रवक्ता के हवाले से बताया गया है कि मकुइलॉंगडी क्षेत्र में, जो ओकलॉंग स्थित नामित एनएससीएन कैंप से करीब दो किलोमीटर पश्चिम में है, सशस्त्र कैडरों की मौजूदगी संबंधी विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिलने के बाद असम राइफलस ने क्षेत्र प्रभुत्व गश्त और तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि खुफिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्ट्स से संकेत मिले थे कि सशस्त्र कैडर निर्धारित कैंपों से बाहर हथियारों और वर्दी के साथ घूम रहे थे, जो स्थापित युद्धविराम के नियमों का उल्लंघन है। साथ ही सीजफायर मॉनिटरिंग ग्रुप को



इन उल्लंघनों की औपचारिक जानकारी भी दी गई और इससे जुड़े सुरक्षा संबंधी मुद्दों से अवागत कराया गया। प्रवक्ता के मुताबिक अभियान में मकुइलॉंगडी और



ओकलॉंग गांवों की ओर बढ़ रही असम राइफलस की टुकड़ियों को बड़ी संख्या में लोगों ने रोक लिया, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। असम राइफलस के जवानों

ने अत्यधिक संयम बरतते हुए स्थानीय प्रतिनिधियों से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि अभियान का उद्देश्य केवल सुरक्षा सुनिश्चित करना और क्षेत्र में शांति बनाए रखना है। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया कि संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बिना कोई भी टुकड़ी किसी गांव में प्रवेश नहीं करेगी। असम राइफलस की टुकड़ियों के वापस लौटने के बावजूद रात बड़ी भीड़ कैंप तक पहुंच गई और पत्थरबाजी, संपत्ति में तोड़फोड़ तथा आगजनी की कोशिश की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेनापति पुलिस और सीआरपीएफ को तैनात किया गया। बाद

में लौटते समय भीड़ ने असम राइफलस के वाहनों में तोड़फोड़ की। एक वाहन को आग लगा दी, जबकि दो ट्रकों को पलटकर क्षतिग्रस्त कर दिया। सुरक्षा बलों, मणिपुर पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त प्रयासों से स्थिति पर काबू पा लिया गया और मंगलवार-बुधवार की मध्यरात्रि तक पूरी भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया था। इस बीच एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 6 जुलाई कैंप तक पहुंच गई और पत्थरबाजी, घात लगाकर किए गए हमले, में असम राइफलस के दो जवान शहीद हो गए थे, इसके मामले में तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है।

अमेरिका की रूसी तेल खरीद पर सख्ती : भारत सहित 5 देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ का प्रस्ताव



वॉशिंगटन ● एजेंसी

अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी शुरू की है। अमेरिकी सीनेट में संशोधित बिल पेश किया गया है, जिसमें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। इस बिल का प्राथमिक उद्देश्य रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना है, ताकि यूक्रेन में उसके युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर हो सके। इस प्रस्तावित बिल के दायरे में भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान जैसे देश आ सकते हैं, जिन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जा सकता है। यह बिल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के समर्थन से लाया जा रहा है, जो इसकी कांग्रेस में पारित होने की संभावना को काफी बढ़ा देता है। यदि यह बिल कानून बनता है, तब अमेरिका पहली बार किसी देश पर सिर्फ इसलिए टैरिफ लगाएगा, क्योंकि वह रूस से तेल खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। भारत के संदर्भ में, हाल ही में जून माह में देश ने रूस से रिकॉर्ड 26.1 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा, जो उसके कुल तेल आयात का 52.4 प्रतिशत था। इसका मतलब है कि पिछले महीने

भारत में आयात होने वाले हर दो बैरल तेल में से एक से ज्यादा रूस से आया। रूस लगातार भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है और मई के मुकाबले जून में रूस से तेल आयात में लगभग 39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। इस बिल में रूस के अधिकारियों, उसके शोधें टैंकर बड़े, केंद्रीय बैंक और सरकारी ऊर्जा परियोजनाओं पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। पहले बिल के शुरुआती मसौदे में 500 प्रतिशत टैरिफ का प्रस्ताव था, जिसे बाद में घटाकर 100 प्रतिशत किया गया। हालांकि, रूस से प्राकृतिक गैस खरीदने वाले कुछ यूरोपीय देशों को राहत मिल सकती है। सीनेट में पेश बिल के तहत 15 यूरोपीय देशों को प्रस्तावित 100 प्रतिशत टैरिफ से छूट दी गई है। इन देशों को छूट इसलिए मिली है क्योंकि वे रूस से 15 प्रतिशत से कम प्राकृतिक गैस खरीदते हैं और धीरे-धीरे उस पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। यह बिल अमेरिकी सीनेट में बाइपार्टिसन समर्थन के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस प्रस्ताव पर सहमत हैं। हालांकि, कानून बनने के लिए अभी सीनेट और प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) दोनों से मंजूरी लेनी होगी, जिसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक है।

